कृषि स्टार्टअपः चुनौतियों का समाधान, नए मील के पत्थर कर रहे हासिल

डॉ० ए.के. सिंह

[1]कुलपति, रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (उ.प्र.),

[2.] डॉ०. आरआर बर्मन, सहायक महानिदेशक (कृषि विस्तार), आईसीएआर

[3.] वैज्ञानिक (एसएस), कृषि विस्तार विभाग, आईसीएआर–आईएआरआई, नई दिल्ली

16 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया गया था। सरकार का दृष्टिकोण देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। भारत सरकार ने कल्पना की है कि यह स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसने देश में नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करने के लिए कृषि–व्यवसाय इन्क्यूबेटरों को और प्रोत्साहन दिया है।

सरकार के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए, 16 जनवरी 2016 को एक स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना की घोषणा की गई थी। इसमें 'सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग', 'वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन', और 'ऊष्मायन हेतु उद्योग और अकादमिक भागीदारी' के तीन प्रमुख क्षेत्रों में 19 कार्य मद शामिल थे।

एमएसएमई (माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज) ने 15 लाख प्री सीड फंडिंग सपोर्ट के साथ आइडिया–स्टेज स्टार्ट–अप को बढ़ावा दिया। यह एक स्थापित इनक्यूबेटर इको–सिस्टम स्टार्टअप के माध्यम से किया गया था। वर्तमान में, स्टार्टअप इंडिया के साथ 2500 से अधिक कृषि–स्टार्टअप पंजीकृत हैं।

आईसीएआर का ''राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष'' प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए व्यवस्था प्रदान करता है। आईसीएआर एवं नार्म कृषि–व्यवसाय इन्क्यूबेटरों को सहायता प्रदान करते हुए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं। यह क्षमता निर्माण के लिए मॉड्यूल, दिशानिर्देश और शिक्षण सामग्री के अन्य रूपों में विकसित करके किया जाता है।

आईसीएआर का उद्देश्य उद्यमी कंपनियों के विकास को विचार के स्तर से आत्मनिर्भर सफल व्यवसाय की ओर बढ़ावा देना है। कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण'' (आरकेवीवाई–रफ्तार) को नया रूप दिया है। इसे 2017–18 में नवाचार और कृषि–उद्यमिता के प्रावधान के साथ लॉन्च किया गया था।

इस योजना के 24 रफ्तार एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आरएबीआईज़) बनाए गए हैं। पांच ज्ञान भागीदार, (आईएआरआई, मैनेज, निआम, एएयू, यूएएस, धारवाड़) की स्थ. पना की गई। प्री–सीड स्टेज स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपये तक और सीड स्टेज स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

नाबार्ड और डीएसटी द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए इसी तरह की पहल की गई है। 2500 से अधिक कृषि–स्टार्टअप को छोटे खेत के आकार, खराब बुनियादी ढांचे, कृषि प्रौद्योगिकियों के कम उपयोग और सर्वोत्तम कृषि तकनीक, अत्यधिक उर्वरक और निरंतर कीटनाशक के उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी जैसी चुनौतियों को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली (एनएआरईएस) इन स्टार्टअप्स को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। समर्थन प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की नेशनल इनिशिएटिव ऑफ डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन (निधि) योजना के तहत समर्थित सात टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (एबीआई) शामिल हैं। और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 29 एबीआई स्टार्टअप्स की सफलता में इनक्यूबेशन एक सहायता मुख्य कारण है।

> उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन निकासी, उसी दिन आवेदन, उसी दिन स्वीकृति और उसी दिन नियुक्ति। श्री अटॉर्नी जनरल, फाइल ने 24 घंटे तक का समय नहीं लिया, मानो उसकी बिजली की गति है। वहां किस तरह का मूल्यांकन है?'
>
> –सुप्रीम कोर्ट'

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड' की घोषणा की। 1,000 करोड़ रुपये के फंड का उद्देश्य स्टार्ट–अप की मदद करना और इच्छुक उद्यमियों के विचारों का समर्थन करना है। यह भारत में स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक सक्षम वातावरण प्रदान करता है।

विभिन्न एग्री–स्टार्टअप्स को इस समर्थन से लाभ हुआ है जैसे कि निन्जाकार्ट, डी–हाटम बीजक, इंटेलो लैब, फाइलू, बीगहाट, ई एफएएआरएम, एब्सोल्यूट आदि प्रमुख हैं। पिछले साल एग्रीटेक स्टार्टअप्स ने 47 सौदों के जरिए करीब 684 मिलियन डॉलर जुटाए। कुल मिलाकर, कृषि–प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने 2014 और 2021 के बीच 1 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाई है। यह भारतीय स्टार्टअप के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये आंकड़े हमारे देश के युवा उद्यमी के सपनों को कृषि प्रौद्योगिकी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

अकेले आर.के.वाई.रफ्तार के तहत, 2500 से अधिक कृषि–स्टार्टअप को कृषि क्षेत्र में समस्याओं जैसे छोटे खेत का आकार, खराब बुनियादी ढांचा, कृषि प्रौद्योगिकियों का कम उपयोग और सर्वोत्तम कृषि तकनीक, मिट्टी की उर्वरता में कमी का, अति–निषेचन और आदि को निरंतर कीटनाशकों का उपयोग हल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में, नासकॉम द्वारा हर साल बताई गयी स्टार्टअप्स की विकास दर 25 प्रतिशत है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स अब देश में एक अत्यधिक सफल क्षेत्र हैं।

फलता–फूलता भारतीय स्टार्टअप इको–सिस्टम

जनवरी 2016 में एक 19–बिंदु ''स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान'' शुरू किया गया था। इसने नवाचार और स्टार्टअप (जीओआई, 2016) के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कई नीतिगत पहलों को सक्षम किया। इससे कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, जैव प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, फिन–टेक, परिवहन, फैशन, पर्यावरण विज्ञान, कानूनी सेवाओं, रसद, आईटी सेवाओं, बाजार आदि जैसे विविध क्षेत्रों में नवीन विचारों वाली नई कंपनियों को शामिल करने में भारी उछाल आया। प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप उर्फ तकनीकी स्टार्टअप में उत्साहजनक वृद्धि देख रहे हैं।

भारत में रोजाना लगभग 3–4 टेक स्टार्टअप पैदा होते हैं (इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, 2020)। स्टार्टअप्स के विकास में प्रमुख बाधा बाजार तक पहुंच है। नवाचार को बाजारों तक पहुंच के साथ मिलाने की जरूरत है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में स्टार्टअप्स में सहयोगात्मक कार्य पर्यावरण की भूमिका, बाजार के आकार और बाजार की उभरती जरूरतों के बारे में जागरूकता से निर्धारित होता है।

प्रभावी निर्णय लेने के लिए, सरकार को सभी हितधारकों को बातचीत के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कंपनियों और किसानों के बीच पारस्परिक लाभ की प्रणाली को सक्षम करेगा। भारत में कृषि स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं की जांच की जा सकती है।

1. किसानों और अन्य हितधारकों के बीच कृषि स्टार्टअप के बारे में जागरूकता बढ़ाना
2. एग्री स्टार्टअप्स के अप–स्केलिंग को सक्षम करने के लिए वित्त पोषण सहायता प्रदान करना ।
3. आईसीएआर संस्थानों/एसएयू द्वारा प्रौद्योगिकी सहयोग और सहायता ।
4. आईसीएआर द्वारा प्रमाणन/प्रौद्योगिकी ऊष्मायन के लिए नवाचारों का परीक्षण और सत्यापन ।
5. माल और सेवाओं के आउट स्केलिंग के लिए एग्री स्टार्टअप्स के बीच नेटवर्किंग और मार्केट लिंकेज बढ़ाना ।
6. एग्री स्टार्टअप्स में नए बाजार स्थान के निर्माण के लिए सार्वजनिक और निजी फर्मों के बीच व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देना ।
7. कृषि में स्टार्टअप विकास को प्रोत्साहन ग्रामीण कृषि और गैर–कृषि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के कई अवसर प्रदान करता है। यह ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के लिए नौकरी के अवसर भी पैदा करता है।